मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

शहर में कुत्तों का खौफ़, मेनका कहे प्रशासन रहे बेखौफ़ एन एच-3 अस्पताल उस लड़की की तरह जिसका न मायका न ससुराल 3

रोज़गार आंकड़े बोलते हैं... सरकारी क्षेत्र में बढ़ रही ठेकेदारी प्रथा 5

''बेटी बचाओ–धर्म बचाओ अभियान'' यानी साम्प्रदायिकता फैलाओ अभियान 6

ई एस आई में श्रमिक रहेंगे बेहाल, निजी अस्पताल होंगे मालामाल अब ई एस आई सी का असल एजेंडा है चिकित्सा व्यापारियों को पालना 8

वर्ष 28 अंक 3 फरीदाबाद, मंगलवार, 16-31 दिसम्बर 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

सी बी आई को प्रधानमंत्री चलायेगा या गोश्त व्यापारी

सी बी आई के 'इस्तेमाल' को लेकर नरेन्द्र मोदी-अमितशाह सरकार भी उसी तरह 'चुस्त' दिखती है जैसे सोनिया गांधी-मनमोहन सरकार हुआ करती थी। ठोक बजा कर विश्वस्त प्यादों को सी बी आई में भरने का सिलसिला जारी है। बदले में ये प्यादे अपने बादशाहों के राज के रास्ते में आ सकने वाले तमाम रोड़ों को हटाने का काम अंजाम देते रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर सी बी आई-वार और ममता का मोदी-अमित शाह पर पलटवार इसी हकीकत को दिखाता है।

मजदूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

बदनाम रंजीत सिन्हा के बाद सी बी आई का डायरेक्टर अनिल सिन्हा को बनाया गया है। रंजीत सिन्हा के पूर्ववर्ती ए पी सिंह को अब छुपा रूस्तम माना जाने लगा है। यानी रंजीत सिन्हा बदनाम तो बहुत हुआ पर कमाई में ए पी सिंह उससे 10 गुणा आगे था। नये डायरेक्टर के बारे में अभी से कहा जा रहा है कि वह रंजीत सिन्हा को भी अच्छा कहलवा कर जायेंगे।

इन तीनों महानुभावों (ए पी सिंह, रंजीत सिन्हा, अनिल सिन्हा) के बीच की साझी कड़ी है रामपुर का गोश्त निर्यातक मोइन कुरैशी। कई राजनीतिकों के लिये दलाली करने वाले कुरैशी ने ए पी सिंह को सी बी आई का डायरेक्टर बनवाने में खासी भूमिका निभाई थी। दरअसल, वर्षों पहले से मोइन सी बी आई में ए पी सिंह, जो वहां स्पेशल डायरेक्टर के पद पर था, के लिये दलाली कर रहा था। इस बीच उसने अपने कांग्रेसी आकाओं के पारस ए पी सिंह का नाम पहुंचाया और उसे मौका आने पर सी बी आई निदेशक बनवा दिया।

ए पी सिंह से पहले भी अश्वनी कुमार ने बतौर डायरेक्टर सी बी आई दो वर्ष तक 2 जी घोटाले की फ़ाइलों को दबा कर रखा था। पूर्व एस पी जी अधिकारी अश्वनी कुमार को स्वयं भी 10 जनपथ (राहुल, प्रियंका राबर्ट वाड्रा) की कृपा से ही सी बी आई की गद्दी मिली थी। बतौर डी जी पी हिमाचल प्रदेश उसने प्रियंका और वाड्रा को शिमला के आसपास ज़मीने हथियाने में मदद पहुंचाई थी।

ए पी सिंह का कार्यकाल जब समाप्ति की ओर बढा तब तक 2 जी के अलावा कोयला घोटलों से राजनीतिक फ़िज़ा खूब गर्म हो चुकी थी। सिंह को अपने कारनामों पर पर्दा डालने वाला उत्तराधिकारी चाहिये था और मोइन कुरैशी को अपनी दलाली चलाते रहने वाला अफ़सर। रंजीत सिन्हा जो ए पी सिंह का बैचमेट है, इस काम के लिये 'उपयुक्त' सिद्ध हुआ। सिन्हा बहुत पहले भी सी बी आई में एस पी रेंक में काम कर चुका था। उस दौरान चारा घोटलों में लालू प्रसाद यादव की मदद करके वह इस कदर बदनाम हुआ कि उसे दोबारा सी बी आई में किसी ने घुसने नहीं दिया। लेकिन अब पत्ते उसके माफ़िक थे।

शेष पेज दो पर

सी बी आई की रफ़्तार कभी टाल कभी तलवार

अपने राजनीतिक आकाओं के लिये सी बी आई को न ढाल बनते देर लगती है न तलवार बनते। अनेकों मामले हैं जहां बरसों तक फ़ाइलें इस लिये लटका कर रखी जाती हैं कि अपने आकाओं को दूसरों को ब्लैक–मेल करने की सुविधा दी जा सके। मायावती, मुलायम सिंह, जयललिता, शिबु सोरेन आदि के मामले इस श्रेणी में आते हैं। 2 जी एवं कोयला घोटाले इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे सरेआम लूट के मामलों को ठंडे बस्ते में रख कर दोषी आकाओं का दामन बेदाग़ रखा जाता है।

इसी के बरक्स ऐसे मामले भी हैं जहां सी बी आई की रफ़्तार देखते ही बनती है। क्योंकि आकाओं के विरोधियों को धूल चटानी होती है। कांग्रेसी राज में ए पी सिंह जैसे भ्रष्ट डायरेक्टर के रहते, आंध्र के जगन मोहन रेड्डी को लाइन पर लाने के लिये उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की झड़ी लगा दी गयी। वैसे ये मामले गलत नहीं थे पर इन्हें तेज़ी से सिरे चढाने की वजह राजनीतिक थी। इसी तरह मोदी सरकार में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ़ सारदा मामले में सी बी आई द्वारा बेहद तेज़ी से कार्यवाही की जा रही है। उद्देश्य, ममता को बंगाल में सत्ता से हटाना और भाजपा को स्थापित करना। सारदा मामलों की देख–रेख अब डायरेक्टर सी बी आई बनाये गये अनिल सिन्हा के हाथों में रही है।

खाप की नैया: नये खिवैया, खट्टर भैया

हरियाणा को कन्या भ्रूण–हत्याओं का प्रदेश बनाने में खापों की भूमिका से सभी परिचित हैं। इसके चलते, खाप प्रभाव वाले गांवों में शादी के लिये लड़कियों का अकाल पड़ गया है और आम चलन है बिहार, केरल एवं सुदूर उत्तर–पूर्व के राज्यों से लड़कियां खरीद कर युवकों का घर बसाने का। पर वोटों का गणित कुछ ऐसा है कि हर पार्टी का राजनेता खापों को चरित्र प्रमाणपत्र देना अपना प्रथम कर्त्तव्य मानता है।

चौटालों के राज में तो खापों की खुली चौधर थी ही। हुड्डा ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने ही अवसरों पर खापों की प्रशंसा की होगी। अब भाजपाई और संघी मेल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी वही भाषा बोलनी शुरू कर दी है। खापों द्वारा लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल फ़ोन रखने पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग का सीधा समर्थन तो खट्टर के बस की बात नहीं है। लिहाज़ा वे खापों को त्वरित न्याय प्रणाली का एजेंट बता कर इसकी भरपाई कर रहे हैं।

खट्टर की माने तो हरियाणा की खापें सैंकड़ों साल से आपसी झगड़ों एवं विवादों को सुलझाने की एक निष्पक्ष और सस्ती सुलभ प्रणाली है। इसे चलाने वाले 30 से 50 साल का अनुभव रखने वाले बुजुर्ग लोग होते हैं। उनके निर्णयों से ही गांवों में आपसी भाईचारा बना रहता है। इस बखान में खट्टर बड़ी सफ़ाई से कन्या भ्रूण हत्याओं और 'इज्जत' हत्याओं का उल्लेख करना भूल गये, जो खापों की सहमति और हशारे पर होती हैं। प्राय: मासूम तर्क दिया जाता है कि यह सब व्यक्ति करते हैं न कि खाप। अगर ऐसा ही है तो इन हत्याओं को रोकने के लिये खाप कोई पहल क्यों नहीं करतीं? ऐसे हत्यारों को गांव बहिष्कृत या सामाजिक प्रताड़ना के दायरे में क्यों नहीं लाते?

यह भी स्पष्ट है कि आज के हरियाणा में विवादों को निपटाने में खापों की भूमिका बेहद कमज़ोर हो गयी है। अन्यथा गांव–गांव में आये दिन मारपीट एवं कत्ल की वारदातें न होतीं। ग्रामीण समाज पर उनकी कोई नैतिक पकड़ भी हो, यह भी संदेहास्पद है। बलात्कार, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ जैसे अपराधों की रोकथाम में खाप किंचित भी भूमिका नहीं निभा पाते। खट्टर द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र मिलने से वे कोई सुधरने नहीं जा रहे।

ख़बर दार

काला धन: डाल-डाल पर यादव सिंह

पिछले कुछ दिनों से नौयडा के चीफ़ इन्जीनियर यादव सिंह मीडिया में छाये हुए हैं। जितना–जितना ढूढते हैं उतना–उतना काले धन का अम्बार निकलता जाता है। शुरू में यह अनुमान एक हज़ार करोड़ था जो अब कई हज़ार करोड़ का होता दिख रखा है। 50 करोड़ तो कोठी की कीमत ही आंकी जा रही है।

जूनियर इन्जीनियर से चीफ़ इन्जीनियर के पद पर पहुंचे यादव सिंह न केवल आज की अखिलेश–मुलायम सरकार के चहेते हैं बल्कि पूर्व माया सरकार के भी बेहद लाडले रहे हैं। इन नेताओं का लाडला चहेता केवल वही हो सकता है जो इन्हें अधिक से अधिक लूट का माल ला–ला कर देवे।

इस देश में जहां हर शहर की डाल–डाल पर यादव सिंह बैठे हैं वहां मात्र एक यादव सिंह को पकड़ कर यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि सरकार ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि किसी भी शहर के चीफ़ इन्जीनियर, चाहे वह नगर निगम का हो या डी डी ए जैसे किसी संस्थान का, पकड़ लो, वह हज़ार करोड़ से कम का नहीं मिलेगा दूर जाने की जरूरत नहीं हरियाणा में 'हूडा' (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) का शायद ही कोई इन्जीनियर 100–200 करोड़ से कम का हो और चीफ़ इन्जीनियरों का तो कहना ही क्या, कोई भी 500 करोड़ से नीचे का नहीं। लगभग यही हाल नगर निगमों व अन्य विभागों के इन्जीनियरों का है।

भ्रष्टाचार की पूंजी, सफलता की कुंजी

इन्जीनियरों द्वारा की जाने वाली सरकारी पैसे की लूट को समझना कोई मुश्किल नहीं। बदरपुर बार्डर से कैली गांव तक बने बाईपास रोड को बनाने में 'हूडा' के भ्रष्टाचारियों ने 6 वर्ष में 129 करोड़ रुपये खर्च किये दिखाये हैं। इस 6 वर्ष के पहले जो गत 20 वर्षों में इसी सड़क पर खर्च हुआ वह अलग से। 'हूडा' के इन भ्रष्टाचारियों से कोई यह पूछने वाला नहीं कि मात्र 30 किलोमीटर की इस सड़क पर इतना खर्च कैसे हो गया? यह तो अभी इनकी मेहरबानी होगी जो 129 करोड़ रुपयों पर ही खाता बन्द कर दे, वरना 229 करोड़ भी खर्च कर दें तो कौन पूछनेवाला है।

इसी तरह ओल्ड फ़रीदाबाद चौक से एन आई टी को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास पर 32 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं लेकिन खर्च–खाता अभी बन्द करने का कोई इरादा भ्रष्ट इन्जीनियरों का नहीं है। विदित है कि शहर में मैट्रो रेल प्रोजेक्ट से पहले इस अंडरपास का काम शुरू हुआ था। मैट्रो रेल का इतना बड़ा और कठिन काम पूरा होने को आ गया लेकिन अंडरपास का छोटा सा काम पूरा होने में नहीं आ रहा। इस देश में कोई यह पूछने वाला नहीं इन चोरों से कि वे गत 5 वर्षों से यह क्या खेल तमाशा कर रहे हैं? खर्चा 8 करोड़ दिखाये या 32 या 40 कोई पूछने वाला नहीं। दरअसल जो पूछने वाले हैं वे भी चुप रहने के एवज में अपना हिस्सा वसूल लेते हैं।

अंडरपास पर इतना भारी खर्च होने के बावजूद ज़रा सी बारिश होने पर इसमें पानी भरना निश्चित है, ठीक उसी तरह जैसे एन टी पी सी चौक से ग्रीन फ़ील्ड कॉलोनी के बीच बने अंडरपास पर भरता है, और रास्ता बंद हो जाता है। ओल्ड फ़रीदाबाद के इस अंडरपास को जलभराव से मुक्त करने के नाम पर अभी नया कारोबार ही शुरू हो जायेगा। लेकिन मुक्ति मिलेगी तब भी नहीं जैसे एन टी पी सी वाले अंडरपास पर गत 30 वर्षों में भी नहीं मिली है।

विकास के नाम पर किये जाने वाले हर काम पर हर विभाग द्वारा यही गोलमाल हो रहा है। विकास के नाम पर खर्च दिखाई जाने वाली कुल राशि का मात्र चौथाई भाग ही सही ठिकाने पर लगता है शेष तीन चौथाई भाग काला धन बन कर यादव सिंहों की जेबों में चला जाता है। मनमोहन सरकार के रेल मंत्री पवन बंसल के समय एक इन्जीनियर ने एक पद विशेष पाने के लिये करोड़ों की रिश्वत इसी लिये तो दी थी कि वह अरबों लूट सके। सरकारी निर्माण कार्यों में खुली लूट में इन्जीनियरों का नाम तो केवल यादव सिंह के संदर्भ में केन्द्रित किया गया है, वरना लूट के इस धंधे में तमाम अफ़सरशाह व राजनेता जुटे हुए हैं और सभी एक दूसरे की कमर खुजाने में जुटे हैं। देश के पाखंडी नेता विदेशों से काला धन लाने की नाटकबाज़ी को छोड़ कर यदि देश में ही पनप रहे काले धन के पहाड़ के इस अनवरत श्रोत को काबू कर लें तो भी गनीमत है।